नईदुनिया

भोपाल, 23 अगस्त 2026

## खास-खबरें

### निर्गम राशि के इस्तेमाल की निगरानी और जानकारी देने से जुड़े नियमों की समीक्षा कर रहा सेबीः तुहिन कांत

**नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः** सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने शनिवार को कहा कि पूंजी बाजार नियामक निर्गम से जुटाई गई राशि के इस्तेमाल की निगरानी और जानकारी देने से जुड़े नियमों की समीक्षा कर रहा है। सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने यहां इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के वार्षिक निदेशक सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य समय पर जानकारी उपलब्ध कराना और अनुपालन प्रक्रिया को सुगम बनाना है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए तुहिन कांत पांडेय ने कहा कि पारदर्शिता का मतलब केवल किसी कंपनी द्वारा दी गई।

### बिना तोड़फोड़ और इंस्टॉलेशन के दीवार पर बना सकेंगे स्मार्ट टीवी स्क्रीन

**नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः** घर में बड़ी स्क्रीन वाला टीवी लगाने के लिए अब भारी खर्च और दीवार पर बदलाव करने की जरूरत नहीं होगी। मिनी प्रोजेक्टर जैसे आधुनिक गैजेट की मदद से किसी भी खाली दीवार को स्मार्ट टीवी स्क्रीन में बदला जा सकता है। मिनी प्रोजेक्टर छोटे आकार का ऐसा उपकरण है, जो मोबाइल, लैपटॉप या अन्य डिवाइस से कनेक्ट होकर वीडियो, फिल्म और अन्य सामग्री को बड़ी स्क्रीन पर दिखा सकता है। इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है और इस्तेमाल के बाद हटाया भी जा सकता है। इन प्रोजेक्टर की खास बात यह है कि इन्हें लगाने के लिए दीवार पर किसी तरह की ड्रिलिंग या स्थायी इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं होती। उपयोगकर्ता अपनी जरूरत के अनुसार कमरे की किसी भी साफ सतह पर बड़ी स्क्रीन का अनुभव ले सकते हैं।

मिनी प्रोजेक्टर में वायरलेस कनेक्टिविटी, एचडी रिजॉल्यूशन और स्मार्ट फीचर्स जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। कई मॉडल में मोबाइल एप और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का सपोर्ट भी मिलता है। इससे उपयोगकर्ता घर पर फिल्म देखने, गेम खेलने और प्रेजेंटेशन जैसे काम आसानी से कर सकते हैं। बड़ी स्क्रीन वाले स्मार्ट टीवी की तुलना में मिनी प्रोजेक्टर कम जगह लेते हैं और इन्हें जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है। खासतौर पर छोटे घरों या उन जगहों के लिए यह उपयोगी विकल्प बन रहे हैं, जहां बड़ा टीवी लगाना संभव नहीं है। तकनीक के विकास के साथ मनोरंजन उपकरणों में भी बदलाव आ रहा है। अब लोग कम जगह में ज्यादा सुविधाएं देने वाले स्मार्ट गैजेट्स को पसंद कर रहे हैं। मिनी प्रोजेक्टर इसी बदलाव का एक उदाहरण है, जो दीवार को ही बड़ी स्क्रीन में बदलने की सुविधा देता है।

### ईपीएफओ ने शुरू किया कर्मचारी नामांकन अभियान, 31 अक्टूबर तक मिलेगा मौका

**नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः** कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने प्रतिष्ठानों से कर्मचारी नामांकन अभियान 2026 का लाभ उठाने की अपील की है। यह अभियान 29 जून 2026 से प्रभावी है और इसके तहत उन पात्र कर्मचारियों को ईपीएफ कवरेज से जोड़ने का अवसर दिया जा रहा है, जो 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2026 के बीच इससे बाहर रह गए थे। ईपीएफओ के अनुसार, यह एक बार मिलने वाला विशेष अवसर है, जिसका उद्देश्य नियोक्ताओं को स्वैच्छिक अनुपालन के लिए प्रोत्साहित करना और पात्र कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है। अभियान 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगा।

इस योजना के तहत पात्र नियोक्ता उन कर्मचारियों की घोषणा कर सकते हैं, जो निर्धारित अवधि के दौरान ईपीएफ कवरेज से बाहर रहे थे और घोषणा की तारीख तक प्रतिष्ठान में कार्यरत हैं। अभियान के माध्यम से पुराने अनुपालन को नियमित करने के लिए कुछ विशेष छूट भी उपलब्ध कराई गई हैं।

ईपीएफओ ने बताया कि नियोक्ताओं को नामांकन और भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी करनी होगी। प्रत्येक घोषित कर्मचारी के लिए उमंग ऐप के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन आधारित यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) तैयार किया जाएगा। इसके बाद अंशदान इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न (ईसीआर) के माध्यम से जमा किया जाएगा।

इस अभियान का उद्देश्य कर्मचारियों को भविष्य निधि, पेंशन और बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना है। ईपीएफओ ने नियोक्ताओं से अपने रोजगार और वेतन रिकॉर्ड की समीक्षा कर पात्र कर्मचारियों की पहचान करने को कहा है।

# इसरो अब नहीं बनाएगा रॉकेट, प्राइवेट कंपनियों को सौंपेगा लॉन्च व्हीकल निर्माण का काम

## पीएसएलवी और एलवीएम-3 जैसे रॉकेटों का उत्पादन निजी क्षेत्र संभालेगा, अंतरिक्ष क्षेत्र में नई भूमिका निभाएगा इसरो

**नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः** भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) अब रॉकेट निर्माण के काम से धीरे-धीरे पीछे हटने की तैयारी कर रहा है। भविष्य में पीएसएलवी और एलवीएम-3 जैसे बड़े लॉन्च व्हीकल के निर्माण की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र की कंपनियों को दी जा सकती है। इस बदलाव का उद्देश्य भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ाना और लॉन्च व्हीकल निर्माण को औद्योगिक स्तर पर विस्तार देना है।

इसरो की भूमिका अब केवल रॉकेट बनाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि संगठन अंतरिक्ष अनुसंधान, नई तकनीकों के विकास और भविष्य के मिशनों पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगा। लॉन्च व्हीकल निर्माण का काम निजी कंपनियों को सौंपने से देश में अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पीएसएलवी भारत का सबसे भरोसेमंद प्रक्षेपण यान रहा है। इसके माध्यम से भारत ने कई उपग्रहों को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किया है। वहीं, एलवीएम-3 इसरो का भारी प्रक्षेपण यान है, जिसका इस्तेमाल बड़े उपग्रहों और मानव अंतरिक्ष मिशनों के लिए

किया जाता है।

अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने हाल के वर्षों में कई कदम उठाए हैं। निजी कंपनियों को रॉकेट निर्माण और उपग्रह प्रक्षेपण जैसी गतिविधियों में अवसर दिए जा रहे हैं। इससे अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में निवेश और प्रतिस्पर्धा बढ़ने की संभावना है। इस बदलाव के तहत निजी कंपनियां इसरो की तकनीकी विशेषज्ञता और अनुभव का लाभ लेकर लॉन्च व्हीकल तैयार कर सकेंगी। इससे रॉकेट उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की अंतरिक्ष सेवाओं का विस्तार हो सकेगा। इसरो लंबे समय से भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का नेतृत्व करता रहा है। संगठन ने उपग्रह प्रक्षेपण, चंद्र मिशन, मंगल मिशन और मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम जैसे कई महत्वपूर्ण अभियानों में सफलता हासिल की है। अब नई व्यवस्था में इसरो की जिम्मेदारी अत्याधुनिक तकनीक विकसित करने और नए अंतरिक्ष अभियानों को आगे बढ़ाने की होगी। निजी क्षेत्र को रॉकेट निर्माण की जिम्मेदारी देने से भारत वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। आने वाले समय में देश में अधिक कंपनियां अंतरिक्ष क्षेत्र में काम कर सकेंगी और लॉन्च सेवाओं का विस्तार हो सकेगा।

# 40 लाख कारें वापस मंगाने का आदेश, टेस्ला की 29.8 लाख गाड़ियां शामिल

**बीजिंग, एजेंसीः** चीन के रेग्युलेटर ने सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए टेस्ला और कई प्रमुख चीनी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों की 40 लाख से ज्यादा गाड़ियां वापस मंगाने का आदेश दिया है। यह इस साल का सबसे बड़ा ऑटो रिकॉल बताया जा रहा है। कार्रवाई मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों में लगे फ्लश या हिडन डोर हैंडल से जुड़ी तकनीकी खामियों को लेकर की गई है। चीन के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मार्केट रेगुलेशन के अनुसार, अमेरिकी वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला चीन में बनी और आयात की गई करीब 29.8 लाख इलेक्ट्रिक कारों को वापस मंगा रही है। इसमें मॉडल 3, मॉडल वाई, मॉडल एक्स और मॉडल एस जैसे वाहन शामिल हैं। कंपनी इस समस्या को सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से ठीक करेगी, जिससे दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। रेग्युलेटर ने बताया कि गंभीर टक्कर या हादसे के बाद यदि वाहन का इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल हो जाता है तो हिडन डोर हैंडल काम करना बंद कर सकते

**हिडन डोर हैंडल में सुरक्षा खामी के चलते कार्रवाई, 2027 से ऐसे हैंडल पर प्रतिबंध की तैयारी**

हैं। इससे वाहन के अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकलने में परेशानी हो सकती है और बचाव दल को भी दरवाजा खोलने में दिक्कत आ सकती है। चीन सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाले फ्लश और हिडन डोर हैंडल को लेकर नियम सख्त करने का फैसला किया है। सरकार के अनुसार, अगले साल से इन पर प्रतिबंध की प्रक्रिया शुरू होगी और 2027 तक यह बैन पूरी तरह लागू हो जाएगा। फ्लश या हिडन डोर हैंडल ऐसे दरवाजों के हैंडल होते हैं जो कार की बॉडी के अंदर छिपे रहते हैं और चाबी या हाथ पास ले जाने पर बाहर आते हैं। इनका इस्तेमाल वाहनों की एयरोडायनामिक्स बेहतर करने और कार को प्रीमियम लुक देने के लिए किया जाता है।

# टाटा हैरियर ईवी ने बदला बाजार का रुख

## पेट्रोल-डीजल मॉडल से ज्यादा बिक्री

**नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः** टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक एसयूवी हैरियर ईवी ने भारतीय ऑटो बाजार में नया ट्रेंड दिखाया है। कंपनी के पोर्टफोलियो में शामिल इस इलेक्ट्रिक वाहन की मांग इतनी बढ़ गई है कि इसकी बिक्री पेट्रोल और डीजल से चलने वाली हैरियर एसयूवी से ज्यादा दर्ज की गई है। टाटा मोटर्स लगातार इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में अपनी स्थिति मजबूत कर रही है। कंपनी के पास देश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कारों की रेंज मौजूद है। हैरियर ईवी के आने के बाद ग्राहकों की पसंद में बदलाव देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में लोग पारंपरिक ईंधन वाले वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक एसयूवी को प्राथमिकता दे रहे हैं।

हैरियर ईवी को आधुनिक तकनीक, बेहतर डिजाइन और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ पेश किया गया है। एसयूवी सेगमेंट में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग को देखते हुए इसका प्रदर्शन कंपनी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारतीय वाहन बाजार में लंबे समय से पेट्रोल और डीजल वाहनों का दबदबा रहा है, लेकिन अब इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर ग्राहकों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। ईंधन खर्च में कमी, पर्यावरण को लेकर बढ़ती जागरूकता और इलेक्ट्रिक वाहनों में उपलब्ध नई सुविधाओं के कारण ग्राहक इन्हें विकल्प के रूप में देख रहे हैं। टाटा मोटर्स पहले से ही नेक्सॉन ईवी, पंच ईवी और अन्य इलेक्ट्रिक मॉडलों के जरिए इस क्षेत्र में मजबूत पकड़ बना चुकी है। हैरियर ईवी की सफलता से कंपनी को इलेक्ट्रिक एसयूवी बाजार में और मजबूती मिलने की उम्मीद है।

# एनएचएआई ने शुरू किया 350 रुपये का खास टोल पास, स्थानीय यात्रियों को मिलेगी राहत

**नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः** भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने स्थानीय यात्रियों की सुविधा के लिए 350 रुपये का डिजिटल लोकल पास शुरू किया है। इस पास के माध्यम से पात्र वाहन मालिकों को टोल प्लाजा पर बार-बार भुगतान करने से राहत मिलेगी। यह सुविधा स्थानीय स्तर पर नियमित यात्रा करने वाले लोगों के लिए शुरू की गई है।

एनएचएआई के इस डिजिटल लोकल पास का उद्देश्य उन यात्रियों को सुविधा देना है, जिन्हें रोजाना या बार-बार किसी निश्चित टोल प्लाजा से होकर गुजरना पड़ता है। पास के जरिए पात्र लोग निर्धारित अवधि तक टोल भुगतान की परेशानी से बच सकेंगे। इस पास के लिए आवेदन प्रक्रिया को आसान रखा गया है। वाहन मालिक डिजिटल माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आवश्यक जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध कराने के बाद पात्रता जांच की जाएगी। स्वीकृति मिलने के बाद डिजिटल लोकल पास का इस्तेमाल किया जा सकेगा।

एनएचएआई ने यह सुविधा

**डिजिटल लोकल पास से बार-बार टोल भुगतान से मिलेगी मुक्ति, ऑनलाइन आवेदन की सुविधा**

टोल व्यवस्था को अधिक सुगम और डिजिटल बनाने के उद्देश्य से शुरू की है। इससे स्थानीय यात्रियों को नकद भुगतान या बार-बार टोल शुल्क देने की प्रक्रिया से राहत मिलेगी। साथ ही टोल प्लाजा पर लगने वाली भीड़ और समय की बचत में भी मदद मिलेगी। डिजिटल लोकल पास का लाभ केवल निर्धारित नियमों और पात्रता के अनुसार ही दिया जाएगा। इसके लिए वाहन और यात्रा क्षेत्र से जुड़ी शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा। पात्र वाहन मालिकों को इस सुविधा का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा।

एनएचएआई लगातार टोल व्यवस्था में डिजिटल सुविधाओं को बढ़ावा दे रहा है। फास्टैग के बाद अब डिजिटल लोकल पास जैसी सुविधाओं के माध्यम से यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। इस पहल से स्थानीय लोगों को नियमित यात्रा में सुविधा मिलने की उम्मीद है। खासतौर पर उन लोगों को फायदा होगा, जिन्हें किसी एक मार्ग या टोल प्लाजा से बार-बार गुजरना पड़ता है। डिजिटल लोकल पास से टोल भुगतान प्रक्रिया अधिक आसान और सुविधाजनक हो सकेगी।

# भारत में लॉन्च हुआ 45 वॉट पावर बैंक वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग की सुविधा

**नए पावर बैंक में मिलेंगे कई आधुनिक फीचर, पोर्टेबल डिजाइन के साथ पेश किया गया**

**नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः** भारत में जीएम मॉड्यूलर ने नया मैजएज 45 वॉट पावर बैंक लॉन्च किया है। इस पावर बैंक में वायर्ड और वायरलेस दोनों तरह की चार्जिंग सुविधा दी गई है। कंपनी ने इसे आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पेश किया है।

नए पावर बैंक में तेज चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है, जिससे उपयोगकर्ता अपने स्मार्टफोन और अन्य डिवाइस को कम समय में चार्ज कर सकेंगे। इसमें पोर्टेबल डिजाइन के साथ कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे इसे यात्रा के दौरान आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपनी के अनुसार, यह पावर बैंक

उन यूजर्स के लिए उपयोगी है, जो एक ही डिवाइस से अलग-अलग चार्जिंग विकल्प चाहते हैं। इसमें वायर्ड चार्जिंग के साथ वायरलेस चार्जिंग की सुविधा भी दी गई है। इसके जरिए ऐसे स्मार्टफोन को भी चार्ज किया जा सकता है, जो वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। मैजएज 45 वॉट पावर बैंक को कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ तैयार किया गया है। इसमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे उपयोगकर्ताओं को बेहतर चार्जिंग अनुभव मिल सके। पावर बैंक की बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनियां अब अधिक क्षमता और तेज चार्जिंग वाले उत्पाद बाजार में ला रही हैं। स्मार्टफोन, ईयरबड्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बढ़ते इस्तेमाल के कारण पोर्टेबल चार्जिंग डिवाइस की जरूरत लगातार बढ़ रही है। जीएम मॉड्यूलर का यह नया पावर बैंक इसी बढ़ती जरूरत को ध्यान में रखकर पेश किया गया है।

**गूगल कंपनी भारत में बना सकती है पिक्सल फोन**

# एक्सपोर्ट हब बनाने की तैयारी, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और कंपोनेंट निर्माण पर सरकार का जोर

**नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः** अमेरिकी टेक कंपनी गूगल अपने पिक्सल फोन समेत अन्य डिवाइसेस के उत्पादन का बड़ा हिस्सा चीन से भारत स्थानांतरित कर सकती है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को कहा कि कंपनी एक्सपोर्ट के लिए भारत को एक प्रमुख उत्पादन केंद्र बनाने की दिशा में काम कर सकती है।

वैष्णव ने बताया कि सरकार अमेरिकी कंपनी एपल के साथ भी लगातार बातचीत कर रही है, ताकि आईफोन के अलावा कंपनी के अन्य उत्पादों का निर्माण भी भारत में शुरू किया जा सके। गूगल ने वर्ष 2023 में भारत में अपने पिक्सल 8 फोन की असेंबलिंग शुरू की थी। इसके लिए भारतीय कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजीज फोन असेंबल करने का काम कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, गूगल वर्ष 2027 तक चीन में अपना उत्पादन पूरी तरह बंद कर सकती है। कंपनी पिक्सल फोन के साथ स्मार्टवॉच और वायरलेस ईयरबड्स का उत्पादन भी चीन से हटाकर भारत और वियतनाम में स्थानांतरित करने की योजना बना रही है।

हालांकि, गूगल ने इस संबंध में अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। वहीं, आईटी मंत्री का कहना है कि सरकार गूगल और एपल दोनों कंपनियों के साथ संपर्क में है। सरकार को उम्मीद है कि दुनियाभर के बाजारों के लिए तैयार होने वाले गूगल डिवाइसेस का बड़ा हिस्सा भारत में बनाया जा सकता है। एपल वर्ष 2017 से भारत में आईफोन का उत्पादन कर रही है। टाटा समूह और फॉक्सकॉन जैसी कंपनियों के सहयोग से देश में आईफोन निर्माण तेजी से बढ़ा है। अनुमान के अनुसार, वर्ष 2026 में दुनिया के कुल आईफोन उत्पादन का करीब 26 प्रतिशत हिस्सा भारत में तैयार किया जाएगा।

भारत अब एपल के लिए केवल एक बाजार नहीं, बल्कि एक प्रमुख एक्सपोर्ट हब बन चुका है। देश में बनने वाले आईफोन का बड़ा हिस्सा विदेशों में भेजा जा रहा है। अब सरकार आईफोन के अलावा आईपैड और मैकबुक जैसे अन्य उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में शुरू कराने पर जोर दे रही है। मोबाइल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 62,500 करोड़ रुपये के बजट वाली नई योजना को मंजूरी दी है। यह योजना वित्त वर्ष 2027 से 2031 तक चलेगी। इसका उद्देश्य केवल फोन असेंबलिंग तक सीमित न रहकर मोबाइल कंपोनेंट्स का निर्माण भी भारत में बढ़ाना है।

**स्पेशल खबर** ई-बोर्डिंग पास से मिलेगा इमिग्रेशन क्लीयरेंस, पासपोर्ट स्टैम्पिंग खत्म करने की भी तैयारी

# एक सितंबर से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को मिलेगी डिजिटल सुविधा

**नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः** विदेश यात्रा करने वाले भारतीय और विदेशी यात्रियों के लिए 1 सितंबर से हवाई यात्रा से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर फिजिकल बोर्डिंग पास पर इमिग्रेशन अधिकारियों की मुहर लगाने की अनिवार्यता खत्म करने का फैसला लिया है। नए नियम लागू होने के बाद यात्री अपने स्मार्टफोन में मौजूद ई-बोर्डिंग पास के जरिए इमिग्रेशन क्लीयरेंस ले सकेंगे। हालांकि, यदि कोई यात्री कागज वाला बोर्डिंग पास लेकर आता है तो वह भी पूरी तरह मान्य रहेगा, लेकिन उस पर इमिग्रेशन अधिकारियों की ओर से कोई स्टैम्प नहीं लगाई जाएगी।

अधिकारियों के अनुसार, बोर्डिंग पास पर स्टैम्पिंग की प्रक्रिया के कारण यात्रियों को कई बार लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ता था। इसके अलावा कई बार मुहर सही तरीके से या स्पष्ट नहीं लगने के कारण बोर्डिंग पास को पढ़ने में भी परेशानी होती थी। यात्रियों की सुविधा और प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए यह बदलाव किया गया है।

सुरक्षा जांच के दौरान बोर्डिंग पास पर स्टैम्प लगाने की व्यवस्था पहले ही बंद की जा चुकी है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह के यात्रियों के लिए सुरक्षा जांच की मुहर लगाने की प्रक्रिया कई साल पहले समाप्त कर दी थी। अब केवल इमिग्रेशन काउंटर पर चल रही स्टैम्पिंग व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है।

ई-बोर्डिंग पास एयरलाइन की वेबसाइट या एप के माध्यम से वेब चेक-इन के बाद यात्रियों को मोबाइल पर प्राप्त होता है। इसमें मौजूद क्यूआर कोड या बारकोड को इमिग्रेशन काउंटर पर स्कैन कराकर यात्री आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।

ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन अब भारतीय पासपोर्ट धारकों के पासपोर्ट पर लगने वाली इमिग्रेशन एंट्री और एग्जिट स्टैम्प को भी खत्म करने की योजना पर काम कर रहा है। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। सफल होने के बाद इसे चरणबद्ध तरीके से देश के सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर लागू किया जाएगा।

इस बदलाव से यात्रियों का समय बचेगा, कागजी प्रक्रिया कम होगी और एयरपोर्ट पर डिजिटल सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। भविष्य में भारतीय इमिग्रेशन सिस्टम को पूरी तरह स्वचालित और बायोमेट्रिक आधारित बनाने की तैयारी है। इसके तहत ई-गेट्स और फेस रिकग्निशन तकनीक के जरिए बिना मानवीय हस्तक्षेप के इमिग्रेशन क्लीयरेंस देने की व्यवस्था विकसित की जा रही है।

# बच्चों की निजता मामले में टिकटॉक करेगा 3828 करोड़ रुपये का भुगतान

**वॉशिंगटन, एजेंसीः** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक ने बच्चों की निजता से जुड़े मामले में अमेरिका में 3828 करोड़ रुपये का समझौता किया है। कंपनी ने बच्चों के डेटा और प्राइवेसी को लेकर उठे सवालों के बाद यह कदम उठाया है। टिकटॉक ने इस मामले के निपटारे के लिए बड़ा भुगतान करने पर सहमति जताई है। इसके साथ ही कंपनी ने अपनी नीतियों और सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव करने की बात कही है। यह मामला बच्चों की व्यक्तिगत जानकारी के इस्तेमाल और उनकी ऑनलाइन सुरक्षा से जुड़ा था।

अमेरिका में बच्चों की ऑनलाइन प्राइवेसी को लेकर नियम काफी सख्त हैं। अधिकारियों ने सोशल मीडिया कंपनियों से बच्चों के डेटा की सुरक्षा और उसके सही इस्तेमाल को लेकर विशेष सावधानी बरतने की अपेक्षा की है। मामले के बाद टिकटॉक ने अपनी प्रक्रियाओं में सुधार करने का फैसला लिया है। कंपनी बच्चों के लिए उपलब्ध सुविधाओं और डेटा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रही है।

टिकटॉक दुनिया के सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शामिल है। बड़ी संख्या में युवा और बच्चे इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा को लेकर कई देशों में सोशल मीडिया कंपनियों की निगरानी बढ़ाई गई है।